

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

18 फरवरी

देहरादून: दिनांक: जनवरी, 2016

विषय: जनपद-चमोली एवं बागेश्वर के अन्तर्गत सिमली-ग्वालदम राज्य राजमार्ग कि०मी० 87.00 (ग्वालदम) से कि०मी० 140.00 (बगोली) तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 48.986 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

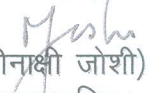
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1011/1जी-3943 (चमोली) दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली एवं बागेश्वर के अन्तर्गत सिमली-ग्वालदम राज्य राजमार्ग कि०मी० 87.00 (ग्वालदम) से कि०मी० 140.00 (बगोली) तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 48.986 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पत्र संख्या-8-23/2014-एफ०सी०/1454, दिनांक 29.09.2015 के द्वारा दी गयी विधिवत् स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित स्थलों पर समतुल्य वन भूमि अर्थात् 49.00 है० (कुलाऊँ बधाणगढ़ी रि०, चिड़िंगा रि०, तलवाड़ी रि०, ग्वालदम रि०, पिण्डरवार रि०, बमियाला रि०, पिण्डरपार सं०-27, नलगॉव एवं बूंगा 2ब) वन भूमि में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
3. Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at project cost, using four feet high RCC pillars, each pillar inscribed with the serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.
4. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road.
5. Sufficient firewood, preferably the fuel shall be provided by the user agency to the labourers. After purchasing the same from the state forest Department of the forest Development corporation or any other legal source of alternate fuel.
6. User agency shall obtain the Environmental Clearance as per the provisions of the Environment (protection) Act, 1986, if required under the said Act.
7. Researchers from the forestry Department of H.N.B. Garhwal University, Srinagar Garhwal or any other University/Research Institute may be allowed to collect measurement/data from trees to be felled from the forest land proposed to be diverted. After collection of data, the researchers may hand over the timber to the State forest Department for its disposal as per the extant procedure.
8. Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry having jurisdiction over the forest land proposed to be diverted may stipulate from time to time for protection and improvement of flora and fauna in the forest area.
9. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिये बाध्य होगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।




11. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
12. Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and not exceeding 3945 and the trees should be felled under strict supervision of the state Forest Department.
13. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
14. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दिखाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल एवं भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों एवं सुझाओं का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
18. मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
19. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
20. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृति के आदेश दिनांक 29.09.2015 में उल्लिखित समस्त शर्तों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

 (मीनाक्षी जोशी)
 अपर सचिव।

संख्या: 979 (1)/ X-4-15/1(498)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली एवं बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. मुख्य अभियन्ता, शिवालिक प्रोजेक्ट, सीमा सड़क संगठन, ऋषिकेश।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

 (आर0के0 तोमर)
 संयुक्त सचिव।

